महामहिम राज्यपाल

श्री गुरमुख निहाल सिंह का अभिभाषण

14, मार्च 1962

अध्यक्ष महोदय और माननीय सदस्यगण,

नई विधान सभा के इस प्रथम सत्र में आपको सम्बोधित करते हुए मुझे बड़े आनन्द का अनुभव हो रहा है। मैं इस अवसर पर आपका स्वागत करता हूँ और आपको मतदाताओं का विश्वास प्राप्त करने की बधाई देता हूँ। हम कुछ ऐसे पुराने सदस्यों के सहयोग से वंचित रह जायेंगे जिन्होंने कि इस सदन के विचार-विमर्श में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मुझे विश्वास है कि नये सदस्य इस उच्च परम्परा को बनाये रखेंगे जो कि अतीत काल में इस भवन सदन की कार्यवाहियों की एक विशेषता रही है।

2. इस महान सभा को सम्बोधित करने का मेरे लिये शायद यह अन्तिम अवसर है क्योंकि आप जानते है मेरा कार्य काल 15 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। अतः मैं अभिभाषण प्रारम्भ करने से पहले यह कहना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि राजस्थान की जनता के प्रति मेरे हृदय में हमेशा प्रेम व सम्मान की भावना रही है और रहेगी। अगर मैं जनता की कुछ सेवायें पिछले साढ़े पाँच सालों में कर सका हूँ, वह मुख्य मंत्रीजी व मंत्रीगण, सरकारी कर्मचारी और जनता के हार्दिक सहयोग से ही हो सकी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जहां भी रहूँगा मुझे हमेशा राजस्थानवासियों का ख्याल रहेगा और मेरे दिल में उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना रहेगी।

3. राज्य विधान मंडलों तथा केन्द्रीय विधान मंडल के गठन के लिये तीसरा आम चुनाव हाल में ही सम्पन्न हुए है जो कि इस देश में लोकतंत्रात्मक संस्थाओं और परम्पराओं की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटना थी। समूचे जन समूह को जो बहुमूल्य अनुभव तथा शिक्षण प्राप्त हुआ है वह सामाजिक निर्णय के इस महान प्रयोग का प्रमुख पहलू है। यह बहुत ही संतोषजनक बात रही कि मतदाताओं का व्यवहार, आमतौर पर बड़ा संयमित रहा और उन्होंने अपने प्रतिनिधियों के चुनाव करने में विशेष दिलचस्पी ली। राज्य में मतदान कार्य केवल 6 दिन के थोड़े समय में ही पूरा हो गया और 82 फीसदी से अधिक निर्वाचकों ने 11,877 मतदान केन्द्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इन चुनावों के सम्पादन में 32000 से अधिक कर्मचारी नियोजित किये गये। मतदान के दौरान, सुरक्षा व व्यवस्था गम्भीर रूप से भंग होने की एक भी घटना की रिपोर्ट नहीं मिली जो हमारी जनता की सद्बुद्धि का परिचय देता है। इस अवधि में, विशेषकर पिछले कुछ महीनों से, राज्य प्रशासन पर वास्तव में असाधारण भार पड़ा और सरकार के लिये तथा व्यक्तिगत रूप से मेरे लिये यह संतोषजनक बात है कि यह महान कार्य सुचारु तथा सुव्यवस्थित रूप से

सम्पन्न हुआ। चुनावों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न हैसियतों में जिस कार्यकुशलता के साथ कर्मचारियों ने अपने कर्त्तव्यों का पालन किया, उसके लिये मैं इस अवसर पर उनकी सराहना करना उचित समझता हूँ।

4. हमने अभी ही योजनाबद्ध विकास के दस वर्ष पूरे किये हैं और तीसरी पंचवर्षीय योजना पर कार्य शुरू कर दिया है। पहली और दूसरी योजनाओं में हमने विशेष रूप से खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, आम लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने, रोजगार के साधन बढ़ाने और शिक्षा तथा चिकित्सा सम्बन्धी बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था करने की कोशिश की है।

5. प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर, राजस्थान में सकल निजी उत्पादन अनुमानतः 408.00 करोड़ रुपये का हुआ था। 1959-60 वर्ष की समाप्ति तक यह 1954-55 के मूल्यों के आधार से 461.00 करोड़ रुपये तक बढ़ गया जिसका अर्थ यह हुआ कि 3.3 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि हुई जब कि इसके मुकाबले उसी समय में अखिल भारतीय औसत वृद्धि की दर 3.1 प्रतिशत थी। राज्य में प्रति व्यक्ति आय 1954-55 के मूल्यों के आधार से 1955-56 में 237.00 रुपये से बढ़कर 1959-60 में 246.00 रुपये होने का अनुमान किया गया है। 1960-61 के मूल्यों पर 1959-60 वर्ष की समाप्ति पर प्रति व्यक्ति आय 315.00 रुपये हो जाने का अनुमान है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, थोड़े ही व्यक्तियों को छोड़ते हुए, अनुमानतः करीब 3.77 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया गया था। गत दस वर्षों में राज्य की कामयाबियों ने, अल्प विकसित अर्थ व्यवस्था में योजनाबद्ध विकास की नीति में हमारा विश्वास दृढ़ कर दिया है तथा उसके प्रभावी होने की बात सिद्ध हो गई है।

6. राज्य में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण योजना को लागू हुए दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में उत्साह की एक बड़ी लहर आ गई है। यह इस बात से भी प्रगट होता है कि 1960-61 में लोगों का विकास कार्यों में योगदान 53,000 रुपये प्रति खण्ड से बढ़कर 1961-62 में 80,000 रुपये प्रति खण्ड हो गया है। स्थानीय निर्माण-कार्यों तथा कार्यक्रमों के बारे में तीसरी पंचवर्षीय योजना को पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों से प्राप्त हुए प्रस्तावों के आधार पर बनाने के प्रयत्न किये गये थे। इस बात को देखते हुए कि यह अपने किस्म का प्रथम प्रयोग था तथा समय भी बहुत ही कम था, लोगों ने इसमें काफी उत्साहपूर्वक योगदान दिया। योजना बनाने की विधि आम जनता को समझाने के लिए पूर्ण प्रयत्न किया जाता रहेगा और ग्राम पंचायतों को अपनी योजनायें तथा उत्पादन कार्यक्रम, ग्राम सभाओं से विचार-विमर्श करके बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। करीब 3,000 गाँवों में लोगों ने अपनी उत्पादन योजनायें तैयार की हैं और कुछ जिलों में, मसलन पाली जहां की सघन कृषि विकास के लिए पैकेज प्रोग्राम प्रारम्भ किया गया है, कुटुम्बवार उत्पादन योजनायें भी तैयार की जा रही हैं।

7. चूंकि विकास तथा प्रशासन सम्बन्धी विभिन्न कार्यों में जनता के प्रतिनिधि काफी बड़ी संख्या में सम्मिलित हो रहे हैं अतः उन्हें पर्याप्त और सामयिक प्रशिक्षण दिये जाने का प्रश्न

अधिक सफलतापूर्ण बन गया है। इस कार्य को राज्य सरकार ने दृढ़तापूर्वक हाथ में लिया और अब [illegible] पंचायत समितियों के करीब 8,500 सदस्य तथा न्याय पंचायतों के 1,000 से अधिक [illegible] प्रशिक्षित किये जा चुके हैं। इस कार्यक्रम को और विस्तृत किया जा रहा है।

8. उत्पादन कार्यक्रमों को सरकार प्राथमिकता दे रही है। इस राज्य के 80 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति कृषि या पशुपालन में लगे हुये हैं या जो व्यक्ति इन कार्यों में लगे हुये हैं उन पर आश्रित हैं। इसलिये इन दो क्षेत्रों में संयुक्त कार्यक्रम की बड़ी आवश्यकता है। बड़ी, मध्यम तथा लघु सिंचाई योजनाओं द्वारा सिंचाई की सुविधायें बढ़ाई गई हैं। शुद्ध सिंचित क्षेत्र 1951-52 में [illegible] लाख एकड़ था जो कि बढ़कर 1958-59 में 35.71 लाख एकड़ हो गया।

9. यथोचित भूमि सुधार, सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि तथा उन्नत कृषि कार्यों के परिणामस्वरूप, राजस्थान में, जहां पहले खाद्यान्न की पैदावार आवश्यकता से कम होती थी, अब आवश्यकता से अधिक होने लगी है। द्वितीय योजना काल में औसत उत्पादन 37.45 लाख टन से बढ़कर [illegible] लाख टन हो गया। भाखरा, चम्बल व राजस्थान नहर की योजनाओं द्वारा अधिक सिंचाई प्राप्त होने पर, हम भविष्य में हमारे देश की खाद्य समस्या को हल करने में सहयोग प्रदान करने की पूर्ण आशा कर सकते हैं।

10. सरकार की नीति के अनुसार सहकारी आन्दोलन को जनता की इच्छानुसार धीरे-धीरे सुदृढ़ बनाया जा रहा है। 1951-52 में सहकारी समितियों की संख्या 4908 थी जो 1960-61 में बढ़कर [illegible] हो गई। 1951-52 में गाँवों की 1.5 प्रतिशत आबादी सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत थी जो 1960-61 में बढ़कर 24 प्रतिशत हो गई है। तीसरी योजना काल में कुल जन संख्या का 67 प्रतिशत अंश सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लिए जाने का प्रयत्न किया जायेगा। सहकारी संस्थाओं द्वारा द्वितीय योजना काल के अन्त तक 1697 लाख रुपये ऋण के रूप में वितरित किये जा चुके थे जो कि प्रथम योजना के आरम्भ की ऋण वितरण संख्या के 11 गुना है। तृतीय योजना काल में सहकारी क्रय-विक्रय के कार्यक्रम के विस्तार के लिये विशेष ध्यान दिया जायेगा।

11. बिजली के साधनों के विकास का औद्योगिक तथा कृषि दोनों ही क्षेत्रों के विकास पर काफी असर होता है। इसीलिये इस कार्यक्रम को योजनाओं में उच्च प्राथमिकता दी गई है। भाखरा और चम्बल जल विद्युत योजनाओं से अधिकाधिक बिजली मिलने से राज्य के काफी बड़े भाग को क्रमशः बिजली की सप्लाई की जा रही है। ऐसे स्थानों पर, जहां किसी भी वर्तमान जल विद्युत योजना से बिजली उपलब्ध नहीं हो रही है, बिजली पैदा करने वाले भाप और डीजल के यंत्रों द्वारा बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिये भी पूरी कोशिश की गई है। सरकार ने राज्य में सहकारी बिजलीघर स्थापित करने की एक योजना अभी हाल ही में मंजूर की है और इस योजना से बहुत से कस्बों और बड़े-बड़े गाँवों को लाभ पहुँच सकेगा। माही और राणा प्रताप सागर बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश

सरकार के साथ मिलकर सलुम्बर पर एक थर्मल पावर स्टेशन बनाने का निश्चय किया है। इस योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है और आशा है जल्दी ही काम शुरू हो जायेगा। इन परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने पर राज्य के बिजली के वर्तमान साधनों में काफी वृद्धि हो जायेगी।

1.2. औद्योगिक विकास के लिये आवश्यक कच्चा माल राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और खनिज पदार्थ भी बहुतायत से मिलते हैं। अभी तक यह प्रान्त सस्ती बिजली, जल, आवागमन के साधन और प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी के कारण अधिक औद्योगिक विकास नहीं कर सका, अब जल और बिजली अधिक प्राप्त होने, परिवहन और संचार साधनों के विकास, ऋण व अनुदानों के जरिये वित्तीय सहायता की व्यवस्था, तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था और उद्योगपतियों को उदारतापूर्वक रियायतें देने के सरकार के निश्चय की वजह से यह राज्य अब एक औद्योगिक युग की ओर चल निकला है। दो नये कारखानों अर्थात् उदयपुर में स्पनिंग मिल्स और कोटा में नाइलोन फैक्ट्री में उत्पादन शुरू हो गया है। किशनगढ़, भीलवाड़ा और भवानीमंडी में कपड़े की मीलों के निर्माण का कार्य संतोषजनक गति से चल रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य को एक लाख पचास हजार स्पिंडिल मिले हैं। जिनका उपयोग न केवल वर्तमान यूनिटों के आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने में, बल्कि राज्य के विभिन्न भागों में दस नई स्पनिंग मिल्स स्थापित करने में भी किया जायेगा। उदयपुर में जिंक स्मैल्टर और चित्तौड़गढ़ में सीमेंट फैक्ट्री की नींव रख दी गई है। हनुमानगढ़ में फर्टिलाइजर फैक्ट्री, कोटा में कैल्सियम कारबाइड, पी.वी.सी. व कास्टिक सोडा प्लांट प्राइवेट सेक्टर में स्थापित किये जायेंगे। आशा है कि उनका निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू हो जायेगा।

1.3. वर्तमान औद्योगिक संस्थाओं का विस्तार हो रहा है और उनमें से कुछ को तो नवीन पदार्थों का निर्माण करने अथवा अपनी औद्योगिक क्षमता बढ़ाने के लिये आवश्यक लाइसेन्स भी मिल गये हैं।

1.4. हाल ही में इस प्रदेश में कुछ बड़े उद्योग स्थापित करने के लाइसेन्स दिये गये हैं जो कि 2-3 वर्ष में चालू हो जायेंगे। उनमें से मुख्य इस प्रकार हैं :-

1. साइन्टिफिक एण्ड सर्जिकल इन्स्ट्रूमेण्ट फैक्ट्री, अजमेर;
2. वूलन मिल्स, जयपुर और जोधपुर;
3. आक्सीजन और एसीटीलिन गैसेज मैन्यूफैक्चरिंग प्लाण्ट, जयपुर;
4. वूल टॉप्स और वूलन फैल्ट्स फैक्ट्री, कोटा;
5. एक्सट्रूजन प्रेस, कोटा;
6. चिप बोर्ड प्लाण्ट, बांसवाड़ा;
7. स्ट्रा बोर्ड प्लांट, कोटा;
8. फैक्शनल एच.पी.मोटर्स मैन्यूफैक्चरिंग इण्डस्ट्री, धौलपुर;

9. ...ट्रीकल पोर्सलेन इन्सूलेटर्स प्लाण्ट्स, जयपुर व कोटा;

10. इलेक्ट्रिकल केबिल फैक्ट्री, कोटा;

11. ...पर मिल, जयपुर;

12. ग्लास वूल एण्ड ग्लास फाइबर फैक्ट्री, जयपुर; व

13. ...र फ्लोर मिल्स, जोधपुर, पाली और उदयपुर।

15. सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कोटा में प्रेसिजन इन्स्ट्रूमेण्ट्स फैक्ट्री और ...में कापर स्मेल्टर प्लांट स्थापित किये जा रहे हैं। राजस्थान सरकार डीडवाना में खारे ... से ...डियम सल्फेट निकालने के लिये भी एक पाइलाट प्लांट स्थापित कर रही है।

16. राज्य सरकार का उन उद्योगपतियों को जो राज्य में निजी क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करके राज्य औद्योगीकरण में सहायता देना चाहते हैं, यथासंभव, सब प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने की नीति पर चलने का विचार है। विशेष रूप से सरकार, लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देना चाहती है। उपलब्ध साधनों की जानकारी के लिए राज्य के अधिकांश जिलों में औद्योगिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। करीब करीब समस्त जिलों में औद्योगिक क्षेत्र अलग ... दिये गये हैं। इन क्षेत्रों में जिनका विकास राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा, नये उद्योग ... करने के लिए समस्त सुविधाएँ, मसलन रियायती दरों पर जमीन व बिजली, दी जायेगी और जल की व्यवस्था की जायेगी। यह भी निश्चित किया गया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक प्रत्येक जिले में सरकार द्वारा चलाये जाने वाले दो औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जायेंगे। ऐसे कई क्षेत्र तो स्थापित हो भी चुके हैं। इनके अलावा, उन क्षेत्रों में जहां ... ने औद्योगिक विकास के प्रति काफी उत्साह दिखाया है विशेष सहायता प्राप्त औद्योगिक ... स्थापित किए जा रहे हैं।

17. खानों के क्षेत्र में विकास संतोषप्रद रहा है। खानों से आमदनी, जो 6 वर्ष पूर्व 50 लाख रुपये से कम थी, अब 1 करोड़ रुपये हो गई है। अधिकांश वृद्धि अधिक उत्पादन के कारण हुई है, रायल्टी की दरों में वृद्धि के कारण नहीं। खान विभाग ने खनिजों का पता लगाने तथा भूगर्भ सम्बन्धी सर्वेक्षण का कार्य जारी रखा है। यह आशा की जाती है कि पलाना लिग्नाइट तथा डूंगरपुर जिले में फ्लोराइट की खानों में से उचित रीति से खनिज पदार्थ निकालने का कार्य राज्य खनिज मंडल जो कि इन खानों की निगरानी के लिए बनाया गया है, के पथ प्रदर्शन में आगामी वर्ष में सफलतापूर्वक शुरू हो जायेगा। भारत सरकार के तेल व प्राकृतिक गैस कमीशन ने जोधपुर में एक यूनिट कायम किया है और जैसलमेर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में तेल निकालने के लिये ड्रिलिंग करने की प्रारम्भिक कार्यवाही शुरू की जा रही है। हमें इस महान प्रयास के सफल होने की पूर्ण आशा है। इससे इस मरूभूमि की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था बदल सकेगी और राज्य तथा देश के साधनों में वृद्धि हो सकेगी।

18. सरकार ने जो एक और सराहनीय कार्य अपने हाथ में लिया है, वह है राज्य अधिकांश लोगों के वास्ते पीने के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था। ऐसी आशा की जाती है तृतीय पंचवर्षीय योजना काल की समाप्ति तक समस्त शहरों में जिनमें 10,000 से अधि आबादी है, तथा इससे कम आबादी वाले कई शहरों में भी वाटर वर्क्स का प्रबन्ध किया सकेगा। कई पंचायतों ने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सहायता के आधार पर समुचित जल प्र की योजना का उत्साहपूर्वक स्वागत किया है। नगरपालिकाओं को अपने क्षेत्र में जल यो स्थापित करने के लिये उत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार एक ऐसी योजना पर वि कर रही है जिसमें कि नगरपालिकाएं स्थानीय जनता से ऋण लेकर अपने क्षेत्र में इस प्रकार योजनाएँ चालू कर सकें। अजमेर में जल व्यवस्था की कठिनाइयों को दूर करने के लिये वि कदम उठाये जा रहे हैं और बीसलपुर बांध से इस शहर को पानी देने की चेष्टा की जा रही राज्य के सूखे भागों में, विशेषरूप से जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में, मीठे पानी की खोज हमें काफी सफलता मिली है और अधिक प्रयास से इस क्षेत्र के लोगों को, जो काफी अरसे त प्रकृति के प्रकोप से पीड़ित रहे हैं, इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में कुछ राहत दे सकेंगे।

19. पिछली दो योजनाओं की अवधि में जनता के लिये चिकित्सा सम्बन्धी सहाय देने का विशेष प्रयत्न किया गया है। जनता को औसत चिकित्सा-सुविधा प्राप्ति के आधार राजस्थान में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर पलंग व संस्थाओं की औसत इस देश में प्राप्त सुवि की इस औसत से आगे बढ़ गई है। यह चेष्टा की जा रही है कि तृतीय योजना काल में हर 8,00 जनसंख्या की इकाई के चिकित्सा के लिये साधन चाहे वे ऐलोपैथिक हों चाहे आयुर्वेदि उपलब्ध किये जायें।

20. शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है। 1950-51 में 6 से 11 वर्ष की आयु 14.8 प्रतिशत बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते थे। 1960-61 में यह प्रतिशत बढ़ कर 45.7 गया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक इस आयु के 68.4 प्रतिशत बच्चों के भ किये जाने की आशा है।

21. पिछले दस वर्ष में 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में स्कूल जाने वाले बच्चों संख्या 5 प्रतिशत से बढ़ कर 13.9 प्रतिशत हो गई है। यह आशा की जाती है कि तृतीय योज काल की समाप्ति तक उक्त आयु के बच्चों में से 24.3 प्रतिशत बच्चे स्कूल जाने लगेंगे।

22. इसी वर्ष आगामी शिक्षा सत्र से जोधपुर में एक नया विश्वविद्यालय खोलने विचार है। जयपुर स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय की अध्यापन शाखा को मजबूत बनाने लिये विश्वविद्यालय को तीन स्थानीय सरकारी कॉलेज हस्तांतरित किये जा रहे हैं।

23. तकनीकी शिक्षा का विस्तार इस तरीके से करने की कोशिश की गई है कि विवि विकास प्रोग्रामों को पूरा करने के लिये आवश्यक योग्य कर्मचारी प्राप्त हो सकें। हमें सिवि

... आवश्यकता से अधिक प्राप्त है लेकिन माइनिंग इन्जीनियरों की कमी को पूरा करने ... और इन्जीनियरिंग कॉलेजों में इस विषय को शुरू किया जा रहा है। इस योजनाकाल ... इन्जीनियरिंग कॉलेज भी खोलना तय हो गया है। डाक्टरों आज कल विशेष कमी ... इस योजना काल में दो और मेडीकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। कृषि और उससे ... विषयों के अध्यापन में सुधार करने के लिये आगामी शिक्षा सत्र में एक 'कृषि ...' उदयपुर में खोलना तय कर लिया गया है। अजमेर में भारत सरकार ने अध्यापकों ... रीजनल ट्रेनिंग कॉलेज खोलने का निश्चय किया है।

24. राज्य में ऐसे सभी छात्रों को जो बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा ली गई परीक्षाओं में ... में पास होते हैं और जिनके संरक्षकों की आमदनी 250/-रुपये प्रति माह से कम है, ... देने की एक व्यापक योजना प्रभावशील है। योग्यता व जरूरत के आधार पर भी ... उदारतापूर्वक दी जाती हैं। वास्तव में योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियां देकर देश में सुलभ ... शिक्षा का लाभ उठाने का अवसर देने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। ... सरकार, ऐसे राजस्थानी छात्र और छात्राओं को जो देश में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में ... करने के लिये तैयार हों, तथा अहिन्दी भाषी क्षेत्रों ऐसे छात्रों को जिन्हें राजस्थान में ... अध्ययन करने का अवसर दिये जाने के लिये सम्बन्धित राज्य सरकारें सिफारिश करें, ... देने का इरादा रखती हैं। भावनात्मक और राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का सूत्रपात ... दिशा में यह एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा।

25. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के हित के लिये बहतर शिक्षा-सुविधाएं, जैसे कि छात्रावास और छात्रवृत्तियां, भूमिहीन व्यक्तियों के लिये पुनर्वास योजनायें, ... सिंचाई योजनायें, पेय जल के कुओं और गृह-निर्माण की योजनायें चालू की गई थीं।

26. सरकार की श्रम कल्याण सम्बन्धी कार्यवाही में सन्तोषजनक प्रगति हुई है। वर्ष के दौरान प्रबन्धकों और मजदूरों के आपसी सम्बन्ध आम तौर पर शान्तिपूर्ण रहे हैं। मजदूरों के लिये अच्छे मकान व अन्य सुविधाएँ देने के लिए विशेष चेष्टा जारी रहेगी।

27. फसल में नुकसान के कारण इस वर्ष अनाज के भाव काफी ऊंचे रहे हैं। यह रबी की फसल अच्छी होने की संभावना से भावों में कुछ गिरावट दृष्टिगोचर है। राज्य सरकार भावों की ... की समस्या के बारे में पूर्ण रूप से जागरूक है और निरंतर यह चेष्टा करती रहेगी कि भाव सीमा से अधिक न चले जायें।

28. गत 10 वर्ष के योजना काल में सड़कों के निर्माण कार्य में काफी वृद्धि हुई है। जबकि सन् 1950-51 में इस प्रान्त में कुल 11,371 मील लम्बी सड़कें थीं द्वितीय योजना काल के बाद सड़कों की कुल लम्बाई 16,744 हो गई।

29. सरकार ने अपनी समस्त सेवा के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित करने व उनमें सुधार लाने की दृष्टि से एक हाइ पावर कमेटी स्थापित की थी। विविध सेवाओं में, एक दूसरे

को समझने और परस्पर सहयोग की भावना रखने के उद्देश्य से तथा दृष्टिकोण की समानता उत्प[न्न] करने के लिये, सभी राज्य सेवाओं और अधीनस्थ सेवाओं के अधिकारियों के लिए, अधिका[री] प्रशिक्षण स्कूल, जोधपुर में फाउंडेशनल कोर्सेज चालू किये गये हैं। इन कोर्सेज में, विवि[ध] सेवाओं के अधिकारियों को सामान्य रूप से ऐसे विषय पढ़ाये जावेंगे, जो कि उनके सेवा-का[ल] में उन्हें उपयोगी सिद्ध होंगे। सभी सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों के लिये नियमित रूप से रिफ्रेश[र] कोर्सेज चालू करने के लिये एक योजनाबद्ध प्रोग्राम भी बना लिया गया है। अधिकारियों [को] विशेष अध्ययन यात्राओं पर अन्य राज्यों में भेजने का भी विचार है।

30. सरकार ने, राज्य के सरकारी कर्मचारियों की वेतन श्रेणियों को और अधि[क] सुव्यवस्थित करने, कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को राहत पहुंचाने व उनकी वेतन-श्रेणि[यों] की जांच करने के उद्देश्य से एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने यह सिफारिश करते हुए ए[क] दरमियानी रिपोर्ट पेश की थी कि ऐसे राज्य कर्मचारियों को जिनकी तनख्वाह कुल मिला [कर] 300/- रुपये और कमी बेशी को ध्यान में रखते हुये 320/- रुपये तक थी, कम वेतन पाने वा[ले] कर्मचारी समझा जाना चाहिये और इन कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को जो महगाई भ[त्ता] मिल रहा है उसमें फिलहाल 5/- रुपये माहवार बढ़ाये जाने चाहियें। सरकार ने यह सिफारि[श] मंजूर कर ली और ता. 1 जुलाई, 1960 से उस पर अमल कर दिया। कुछ समय बाद कमे[टी] ने एक मुकम्मल रिपोर्ट पेश की। कमेटी की इन सिफारिशों पर भी, कुछ परिवर्तन सहित, अम[ल] किया जा चुका है। नये वेतन-क्रम अतीत प्रभावी रूप में यानी 1 सितम्बर, 1961 से लागू [कर] दिये गये हैं। वेतन श्रृंखलाओं की संख्या 135 से घटा कर 36 कर दी गई है। 150/- रुप[ये] माहवार से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता घटा कर 10/- रुपये कर दि[या] गया है व 150/- रुपये से 300/- रुपये और कुछ कमी बेशी के कारण 320/- रुपये पा[ने] वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता घटा कर 20/- रुपये कर दिया गया है। शेष महंगाई भ[त्ता] वेतन के साथ विलीन कर दिया गया है जिससे कि उन्हें पेंशन में अधिक लाभ मिल सके। इस[के] अलावा विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि कम वेतन पाने वाले वर्गों को फायदा पहुंचाने के उद्दे[श्य] से 10 प्रति शत पदों के सिलेक्शन ग्रेड कायम कर दिये गये हैं।

31. कर वसूली के तरीकों को सरल बनाने की चेष्टा की जाती रही है। तब भी रा[ज्य] सरकार यह महसूस करती है कि इसमें और अधिक सुव्यवस्था लाने की गुंजाइश है। इसीलि[ए] यह निर्णय लिया गया है कि एक हाईपावर कमेटी इस मामले की विस्तृत रूप से छानबीन कर[ने] के लिए तुरन्त स्थापित की जाय।

32. कार्य का उच्च-स्तर बनाये रखने, विलम्ब दूर करने व सरकारी दफ्तरों में का[र्य] कुशलता को बढ़ाने की समस्याओं की ओर सरकार निरंतर ध्यान देती रही है। इसी उद्देश्य [से] सचिवालय में आर्गनाईजेशन एण्ड मैथड्स का एक विशेष विभाग स्थापित किया गया है। इ[स] सम्बन्ध में काफी प्रगति हुई है, लेकिन सुधार के लिए गुंजाइश तो सदा ही रहता है। अतएव इ[स]

[illegible] करने और सरकारी काम-काज को अविलम्ब निबटाने के तरीकों पर विचार [illegible] एक विशेष समिति का गठन किया जा रहा है।

[illegible] पिछले वर्ष में सुरक्षा व व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक रही। इस दौरान में 107 [illegible] गये, [illegible] गोली से मारे गये और 2 ने आत्मसमर्पण किया।

[illegible] अतीत में अपनाई गई नीतियों तथा पिछले वर्षों में प्राप्त की गई सफलताओं जिनमें [illegible] नागरिकों ने विशेष रूप से भाग लिया है, के कारण इस राज्य में लोकतन्त्र की जड़ें [illegible] राजनैतिक बल्कि आर्थिक व सामाजिक रूप से भी मजबूत हुई हैं। निस्सन्देह धीरे-[illegible] निश्चित रूप से एक सहकारी कल्याणकारी राज्य का ढांचा बनता जा रहा है परन्तु [illegible] मंजिल बहुत दूर है। जिन कामों को करने का हमने अपने सामने लक्ष्य रखा है वे [illegible] उनको पूरा करने के लिए और अधिक दृढ़संकल्प, त्याग, अनुशासन तथा सहयोग [illegible] आवश्यक है। इसमें संदेह नहीं कि हमारी योजनाओं तथा स्कीमों को कार्यान्वित करने [illegible] हुई हैं और कमियां भी रह गई हैं। किन्तु मनुष्य द्वारा किया जाने वाला कोई ऐसा कार्य [illegible] कि कोई कमी न रह जाय। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, हमारी सफलता के बारे में [illegible] सन्देह नहीं है। हमारा रास्ता कठिन और बाधाओं से परिपूर्ण हो सकता है, किन्तु यदि [illegible] मतभेद समाप्त कर देने का निश्चय कर लें, जनता को अपने कार्यक्रमों में शामिल [illegible] उनका पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त करने के लिये संयुक्त प्रयत्न करें तो निस्सन्देह हम अपने [illegible] प्राप्ति में सफल होंगे। हम लोकतंत्रात्मक जीवन क्रम अपनाने के लिये वचनबद्ध हैं और [illegible] ढांचे में अपने समाज को ढालने के लिए इस सदन के समस्त सदस्यगण के पूर्ण [illegible] आवश्यकता होगी। अतः मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप उस हद तक जहां [illegible] जनसाधारण के कल्याण के कार्यों का प्रश्न है, एक प्रकार से संधि स्थापित कर लें। मुझे [illegible] विवेक और सद्बुद्धि पर पूर्ण विश्वास है और आशा करता हूं कि आप इसमें अपना पूर्ण [illegible] प्रदान करेंगे और सद्भावना सहित मेरे इस निवेदन को स्वीकार करेंगे।

[illegible] अब मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आप को अपने कार्य में सफलता दे। मुझे बिल्कुल [illegible] नहीं है कि आपके विचार-विमर्श एवं वाद-विवाद, लोक-कर्त्तव्य, उत्तरदायित्व तथा [illegible] उच्च-भावनाओं से पूर्ण होंगे और जो निर्णय लिये जायेंगे वे आदान-प्रदान की मनोवृत्ति [illegible] होंगे।

जयहिन्द

✪✪✪